Wisdom Vortex:
International Journal of Social Science and Humanities

Bi-lingual, Open-access, Peer Reviewed, Refereed, Quarterly Journal

e-ISSN: 3107-3808

Wisdom Vortex: International Journal of Social Science and Humanities, Volume: 01, Issue: 03, Oct-Dec 2025

How to cite this paper:
Chourasia, K. P. (2025). Gramin Shiksha ki Gunwatta aur Chunautiyan, *Wisdom Vortex: International Journal of Social Science and Humanities, 01*(03), 06 – 12.

Received: 10 Aug. 2025
Accepted: 30 Sep. 2025
Published: 21 Oct. 2025

Copyright © 2025 by author(s) and Wisdom Vortex: International Journal of Social Science and Humanities.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY- 4.0).
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और चुनौतियाँ

कल्पना प्रसाद चौरसिया [1]

सारांश

यह लेख ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ग्रामीण शिक्षा केवल विद्यालयों की संख्या तक सीमित न होकर, यह उस सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है जिसमें ग्रामीण बच्चे सीखते और विकसित होते हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि भारत में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति यद्यपि नामांकन और साक्षरता दर के मामले में बेहतर हुई है, फिर भी गुणवत्ता, शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल पहुँच और सामाजिक समानता के क्षेत्रों में गंभीर अंतर विद्यमान हैं। प्रमुख अवरोधों में अपर्याप्त अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, डिजिटल डिवाइड, गरीबी, बाल श्रम, लैंगिक असमानता और अभिभावक सहभागिता की कमी शामिल हैं। लेख में विभिन्न सरकारी योजनाओं—जैसे सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना—के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है, साथ ही सफल मॉडलों जैसे सामुदायिक भागीदारी, डिजिटल नवाचार और पंचायत-आधारित शिक्षा प्रबंधन को प्रभावी उपायों के रूप में रेखांकित किया गया है। अध्ययन यह सुझाव देता है कि ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण और नीति-क्रियान्वयन की निगरानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय शोध और तुलनात्मक अध्ययनों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति बनाना भविष्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार, ग्रामीण शिक्षा में सुधार केवल शैक्षिक प्रगति ही नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास का भी प्रमुख आधार बन सकता है।

विशिष्ट शब्द: *ग्रामीण शिक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, अवसंरचना, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, बालिका शिक्षा, नीति-हस्तक्षेप, सामुदायिक सहभागिता, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान*

ग्रामीण शिक्षा का अर्थ केवल गाँव में विद्यालयों की उपस्थिति तक सीमित नहीं है; यह उस शिक्षा-प्रक्रिया, शैक्षिक संदर्भ और सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी का समुच्चय है जिसमें ग्रामीण समुदायों के बच्चे और युवा सीखते, सामाजिक रूप से विकसित होते और रोजगार- एवं जीवन-कौशल प्राप्त करते हैं (Stelmach, 2011)। ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेश के लिए केंद्रीय साधन मानी जाती है क्योंकि यह स्थानीय लोगों की क्षमताओं को सुदृढ़ कर स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी को सशक्त बनाती है (UNESCO, 2004)। इसलिए ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल शैक्षिक नतीजे नहीं सुधारता, बल्कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आधार भी बनता है (UNESCO, 2004; Stelmach, 2011)।

1. भारत में ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा की तुलना

भारत में हाल के दशकों में ग्रामीण शिक्षा में नामांकन और उपलब्धियों में स्पष्ट सुधार देखे गए हैं, परन्तु शहरी क्षेत्रों के साथ तुलना करने पर कई क्षेत्रों में असमानताएँ और अलग-अलग चुनौतियाँ बनी हुई हैं — उदाहरण के लिए अवसंरचना, डिजिटल पहुँच, शिक्षक उपलब्धता और सीखने के परिणामों में

[1] शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय, औरंगाबाद, बिहार

भिन्नता (ASER Centre, 2024)। ASER 2023 जैसे सर्वे यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन दर बढ़ी है और कुछ स्थानों पर प्रदर्शन में सुधार भी हुआ है, पर सीखने की गुणवत्ता (foundational skills) और डिजिटल तत्परता के मामले में ग्रामीण-शहरी अंतर और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का गहरा प्रभाव स्पष्ट है (ASER Centre, 2024)। कुछ हालिया राज्यों/जिलों के सर्वे-नतीजे यह भी दिखाते हैं कि हर जगह का अंतर एक समान नहीं है — कई ग्रामीण क्षेत्र कुछ संकेतकों में शहरी क्षेत्र के बराबर या बेहतर भी कर रहे हैं, जबकि अन्य जगहों पर बड़ी कमी बनी हुई है (Parakh/UDISE रिपोर्ट-आधारित स्थानीय विश्लेषण)। (ASER Centre, 2024; UDISE रिपोर्टें)

इस विषय पर पूर्व शोध का संक्षिप्त अवलोकन : अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने ग्रामीण शिक्षा पर विविध पहलुओं—मल्टीग्रेड कक्षाएँ, शिक्षक-ट्रेनिंग, अवसंरचना, बालश्रम/गरीबी के प्रभाव, डिजिटल डिवाइड और महामारी-कालीन शिक्षण व्यवधान—पर व्यापक साहित्य विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय साहित्य दोनों में यह रेखांकित किया जाता है कि ग्रामीण स्कूलों को विशिष्ट स्थानीय संदर्भों (भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक) के अनुसार नीतिगत और कार्यक्रमगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है (Stelmach, 2011; UNESCO, 2004)। कोविड-19 के बाद डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा की क्षमताओं पर हुए अध्ययनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, उपकरणों की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की सीमाओं को प्रमुख समस्या के रूप में उजागर किया है (Mustafa, 2024; Pratham/ASER, 2024)। साथ ही कई केस-स्टडी और सफल मॉडलों ने सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय भाषा-आधारित शिक्षण तथा लक्षित प्रशिक्षण के प्रभावशील उपायों को रेखांकित किया है, पर व्यापक और तुलनात्मक प्रभाव मूल्यांकन अभी भी सीमित है (Stelmach, 2011)।

अध्ययन का उद्देश्य और फोकस एरिया : इस समीक्षा-लेख का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करना, मौजूदा नीतिगत हस्तक्षेपों और क्षेत्रीय-प्रयोगों का आकलन करना, तथा उन शोध-अंतरालों (research gaps) की पहचान करना है जिन पर आगे के सैद्धान्तिक और व्यवहारिक शोध की आवश्यकता है। इस लेख में विशेष रूप से (a) अवसंरचना और संसाधन, (b) शिक्षक-सम्बंधी मुद्दे, (c) सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ (जैसे गरीबी, लिंग-विसंगतियाँ), और (d) डिजिटल पहुँच एवं इसकी प्रभावशीलता पर केन्द्रित साहित्य-समीक्षा की जाएगी। भौगोलिक फोकस ग्रामीण भारत पर रहेगा, परन्तु तुलना हेतु कुछ अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी शामिल किए जाएंगे ताकि नीतिगत अनुशंसाएँ व्यापक और व्यवहार्य बन सकें (ASER Centre, 2024; UNESCO, 2004; Stelmach, 2011)।

2. ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति (Current Status of Rural Education)

भारत में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति बीते दो दशकों में नीति-हस्तक्षेपों और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से बेहतर हुई है, लेकिन गुणवत्ता, पहुँच और परिणामों के मामले में पर्याप्त अंतर अब भी मौजूद है। साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर कायम है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर लगभग 68.9% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 84.9% दर्ज की गई (Census of India, 2011)। हालिया सर्वेक्षणों जैसे ASER 2023 ने संकेत दिया कि नामांकन दर प्राथमिक स्तर पर काफी ऊँची है—कई राज्यों में 95% या उससे अधिक—लेकिन कक्षा अनुसार सीखने के परिणाम (reading और arithmetic skills) अभी भी कमजोर हैं, विशेषकर निम्न स्तर की कक्षाओं में (ASER Centre, 2024)।

सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों की उपलब्धता ग्रामीण शिक्षा की संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाती है। अधिकांश ग्रामीण बच्चों की प्राथमिक निर्भरता सरकारी विद्यालयों पर ही रहती है, हालाँकि कई राज्यों में निजी एवं NGO संचालित विद्यालय भी उभर रहे हैं (UDISE+, 2023)। सरकारी योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान ने विद्यालय-स्थापना, भवन निर्माण, मिड-डे मील और बालिका शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार लाए हैं, पर शिक्षक अभाव, आधारभूत संरचना की कमी और भाषा-आधारित शिक्षण संसाधनों का अभाव अब भी गंभीर चुनौतियाँ हैं (UNESCO, 2020)।

ग्रामीण शिक्षा की संरचना प्राथमिक (कक्षा 1–5), उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8), माध्यमिक (कक्षा 9–10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12) स्तरों में विभाजित है, लेकिन सभी स्तरों पर विद्यालयों और अध्यापकों की समान उपलब्धता नहीं है। कई दूरस्थ क्षेत्रों में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण छात्र उच्चतर शिक्षा की ओर कम अग्रसर हो पाते हैं (Planning Commission, 2013)। नतीजतन, प्राथमिक स्तर पर उच्च नामांकन होते हुए भी माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर अधिक देखी जाती है (ASER Centre, 2024)।

क्षेत्रीय असमानताएँ ग्रामीण शिक्षा की मौजूदा स्थिति को और जटिल बनाती हैं। उत्तर-पूर्व, मध्य भारत और जनजातीय बहुल राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता दोनों में चुनौतियाँ अधिक गहरी हैं (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भाषा, भौगोलिक दूरी, परिवहन की कमी और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। वहीं कुछ दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पंचायत-आधारित प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और NGO सहयोग के कारण अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक संकेतक दर्ज किए गए हैं (ASER Centre, 2024; UNESCO, 2020)।

समग्र रूप से, ग्रामीण भारत में शिक्षा का आधार मजबूत करने के लिए न केवल संसाधन-सुधार बल्कि सीखने के परिणामों, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल पहुँच और स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने वाली नीतियों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है (ASER Centre, 2024; Mehrotra & Panchamukhi, 2020)।

3. ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Quality)

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता अनेक संरचनात्मक, मानवीय और तकनीकी तत्वों पर निर्भर करती है। अवसंरचना की उपलब्धता, शिक्षकों की उपस्थिति एवं दक्षता, पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता और डिजिटल पहुँच जैसे कारक सामूहिक रूप से सीखने के अवसरों और सीखने के परिणामों को निर्धारित करते हैं।

a. शैक्षिक अवसंरचना (Educational Infrastructure): गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य है। ग्रामीण भारत में कई विद्यालय अभी भी भवन, पर्याप्त कक्षाओं, बिजली, शौचालय और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं (UDISE+, 2023)। यद्यपि सरकारी हस्तक्षेपों ने इन सुविधाओं में सुधार लाने का प्रयास किया है, फिर भी दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में

हालात अधिक चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं (UNESCO, 2020)। शौचालयों की अनुपलब्धता विशेष रूप से बालिकाओं की उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जबकि बिजली और पेयजल की कमी शिक्षण-सीखने के वातावरण को बाधित करती है (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। इसके अलावा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और ICT सुविधाओं की सीमित या असमान उपलब्धता बच्चों को वैकल्पिक संसाधनों, प्रयोगात्मक अधिगम और डिजिटल साक्षरता से वंचित रखती है (ASER Centre, 2024)।

b. शिक्षक से संबंधित चुनौतियाँ: शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता ग्रामीण शिक्षा के सबसे निर्णायक कारकों में से एक है। कई राज्यों में अब भी शिक्षकों की संख्या मांग के अनुरूप नहीं है, जिससे एक शिक्षक को एकाधिक कक्षाओं में पढ़ाना पड़ता है (UNESCO, 2020)। शिक्षक अनुपस्थिति (teacher absenteeism) भी एक स्थायी समस्या के रूप में सामने आती है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ निगरानी और प्रोत्साहन तंत्र सीमित हैं (Kremer et al., 2005)। प्रशिक्षण, सतत व्यावसायिक विकास और स्थानीय संदर्भ की समझ का अभाव शिक्षकों की प्रभावशीलता को सीमित करता है (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। परिणामस्वरूप, छात्र-केन्द्रित शिक्षण और नवाचारपूर्ण विधियों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता।

c. पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ: ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण अधिकतर पारम्परिक पद्धतियों पर आधारित रहता है, जिसमें रटने (rote learning) और व्याख्यान पद्धति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है (ASER Centre, 2024)। आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ, जैसे गतिविधि-आधारित अधिगम (activity-based learning), मिश्रित अधिगम (blended learning) और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण, अभी भी सीमित मात्रा में अपनाए जाते हैं (UNESCO, 2020)। स्थानीय भाषाओं, सांस्कृतिक उदाहरणों और संदर्भ आधारित शिक्षा की उपेक्षा करने से बच्चों के लिए पाठ्य-सामग्री को समझना कठिन हो जाता है, खासकर बहुभाषी और जनजातीय क्षेत्रों में (Mohanty & Panda, 2015)। इससे लर्निंग आउटकम्स (learning outcomes) पर सीधा असर पड़ता है, जिसका प्रमाण ASER रिपोर्टों और राष्ट्रीय आकलन सर्वेक्षणों में मिलता है, जहाँ ग्रामीण बच्चों के पढ़ने और गणितीय क्षमता के स्तर अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए हैं (ASER Centre, 2024)।

d. डिजिटल डिवाइड: डिजिटल संसाधनों की सीमित पहुँच ग्रामीण शिक्षा में उभरती हुई प्रमुख चुनौती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट उपकरण और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाओं का अभाव ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा को बाधित करता है (UNICEF, 2021)। कोविड-19 के दौरान यह अंतर और स्पष्ट हुआ, जब ग्रामीण छात्रों में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ाव काफी कम देखा गया, मुख्यतः संसाधन, तकनीकी कौशल और अभिभावक सहयोग की कमी के कारण (Mustafa, 2024)। कई विद्यालयों में ICT उपकरण या तो उपलब्ध ही नहीं हैं या अप्रशिक्षित शिक्षकों के कारण अप्रयुक्त रह जाते हैं (UNESCO, 2020)। परिणामस्वरूप ग्रामीण बच्चों के डिजिटल साक्षरता कौशल और तकनीकी Exposure में भारी कमी दिखाई देती है, जो 21वीं सदी की सीखने की आवश्यकताओं से उन्हें पीछे कर देती है।

4. सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ (Socio-economic & Cultural Barriers)

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारक गहराई से प्रभावित करते हैं। यद्यपि सरकारी नीतियों और योजनाओं ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया है, फिर भी गरीबी, लैंगिक असमानता, सामाजिक बहिष्करण और अभिभावकों की सीमित सहभागिता के कारण शिक्षा का लाभ समान रूप से सभी तक नहीं पहुँच पाता।

गरीबी और बाल श्रम: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी शिक्षा में निरंतरता और गुणवत्ता के लिए सबसे प्रमुख अवरोधों में से एक है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर घरेलू कार्यों या बाल श्रम में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनकी नियमित उपस्थिति और सीखने की क्षमता बाधित होती है (ILO, 2017)। कई अध्ययनों में पाया गया है कि परिवार की आय, आजीविका की अस्थिरता और ऋण की परिस्थितियाँ बच्चों की स्कूली शिक्षा में व्यवधान का कारण बनती हैं (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। विद्यालय से अनुपस्थिति और प्रारंभिक ड्रॉपआउट अक्सर ऐसे ही आर्थिक दबावों का परिणाम होते हैं।

बालिका शिक्षा से संबंधित चुनौतियाँ: ग्रामीण भारत में बालिकाओं की शिक्षा सामाजिक संरचनाओं, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और अवसंरचना की अपर्याप्तता से प्रभावित होती है। किशोरावस्था में विद्यालय से हटाना, जल्दी विवाह, घरेलू जिम्मेदारियाँ, और सुरक्षित शौचालयों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियाँ बालिकाओं की स्कूली उपस्थिति और निरंतरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं (UNICEF, 2021)। यद्यपि बेटियाँ-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने बालिका शिक्षा को संस्थागत समर्थन दिया है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-आधारित असमानताएँ बनी हुई हैं (ASER Centre, 2024)।

अभिभावक जागरूकता एवं सहभागिता: अभिभावक की शिक्षा, जागरूकता और बच्चों की शिक्षा में उनकी सहभागिता, सीखने की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण परिवेश में शिक्षित अभिभावकों का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे शिक्षा को दी जाने वाली प्राथमिकता कम होती है (UNESCO, 2020)। कई परिवारों में यह धारणा बनी रहती है कि शिक्षा का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सीमित है, जिसके कारण वे बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने या घरेलू अध्ययन हेतु प्रोत्साहित नहीं करते (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। कुछ स्थानों पर सामुदायिक निगरानी समितियाँ और स्कूल प्रबंधन समितियाँ सक्रिय हैं, पर उनकी भूमिका और जागरूकता अब भी सीमित है।

जातीय व क्षेत्रीय असमानताएँ: जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता ग्रामीण शिक्षा के अवसरों को गहराई से प्रभावित करती है। अनुसूचित जनजाति (ST) और कुछ अन्य वंचित समूहों के बच्चों को विद्यालयी पहुँच, भाषा-संबंधी बाधाओं और सामाजिक भेदभाव के कारण विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (Govinda & Bandyopadhyay, 2011)। पर्वतीय, वनांचल और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भौगोलिक दूरी, परिवहन की कमी और स्थानीय भाषा में शिक्षण-सामग्री की अनुपलब्धता शिक्षा की निरंतरता को प्रभावित करती है (UNESCO, 2020)। इसके अतिरिक्त, जातीय असमानताओं के कारण सामाजिक बहिष्करण और भेदभाव भी बच्चों के विद्यालय अनुभव पर नकारात्मक असर छोड़ते हैं (ASER Centre, 2024)।

समग्र रूप से देखा जाए तो सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक बाधाएँ ग्रामीण शिक्षा के संरचनात्मक और मानवीय पक्षों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, जिसके समाधान के लिए नीति, समुदाय और संस्थागत सहयोग की बहुस्तरीय रणनीतियाँ आवश्यक हैं (Mehrotra & Panchamukhi, 2020; UNICEF, 2021)।

5. नीतियाँ, योजनाएँ और हस्तक्षेप (Policies, Programs & Interventions)

ग्रामीण शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और समानता को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र ने समय-समय पर विविध योजनाएँ और हस्तक्षेप लागू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल नामांकन बढ़ाना है बल्कि अधिगम परिणामों, आधारभूत सुविधाओं और शिक्षण वातावरण में सुधार लाना भी है।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA): सर्व शिक्षा अभियान (2001) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस कार्यक्रम का ध्यान नामांकन बढ़ाने, विद्यालय निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और समुदाय की भागीदारी पर केंद्रित रहा (Govt. of India, 2014)। इसके परिणामस्वरूप कई ग्रामीण स्कूलों में भवन, कक्षाएँ और शौचालय जैसी सुविधाओं में सुधार दर्ज किया गया (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। हालाँकि, गुणवत्ता-आधारित सुधार और सीखने के परिणामों पर इसका प्रभाव मिश्रित पाया गया।

समग्र शिक्षा अभियान: 2018 में प्रारम्भ किया गया समग्र शिक्षा अभियान एक एकीकृत कार्यक्रम है, जिसमें SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित करके प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है (Ministry of Education, 2018)। इसका उद्देश्य स्कूल अवसंरचना, ICT एकीकरण, प्रशिक्षित शिक्षक और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना ने डिजिटल लैब, विज्ञान कक्षाओं, पुस्तकालयों और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत में भूमिका निभाई है (UNESCO, 2020)।

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme): मध्याह्न भोजन योजना ने ग्रामीण छात्रों की विद्यालय उपस्थिति, पोषण और सीखने की निरंतरता में सकारात्मक प्रभाव डाला है (Drèze & Goyal, 2003)। यह योजना विशेष रूप से वंचित एवं निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए आकर्षण का माध्यम बनी। अनेक शोधों में पाया गया है कि भोजन उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवारों का विद्यालय पर भरोसा बढ़ा और संतुलित आहार की कमी को आंशिक रूप से पूरा किया जा सका (UNICEF, 2021)।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009) का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और संरचना को मजबूत करना था (Govt. of India, 2014)। विद्यालय उन्नयन, शिक्षक नियुक्ति, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना, और बालिकाओं की माध्यमिक स्तर पर भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण उपाय इस योजना का हिस्सा रहे (UNESCO, 2020)। हालांकि कई जिलों में बुनियादी ढाँचे और शिक्षक उपलब्धता से संबंधित अंतर अब भी बने हुए हैं।

NGO एवं CSR की भूमिका: ग्रामीण शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। कई NGOs भाषा-संबंधी सामग्री, सामुदायिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और जनजातीय शिक्षा पर केंद्रित होकर कार्यरत हैं (Pratham, 2020)। CSR के माध्यम से डिजिटल लैब, छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहलें ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई हैं (FICCI, 2019)। इन पहलों ने कई स्थानों पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार नवाचारपूर्ण मॉडल विकसित किए हैं, हालांकि उनके प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन अभी सीमित है।

समग्र रूप से, इन योजनाओं और हस्तक्षेपों ने ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को विस्तार और संरचना प्रदान की है। फिर भी अवसंरचना, गुणवत्ता नियंत्रण, समुदाय-आधारित निगरानी और प्रभाव के सतत मूल्यांकन की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है (UNESCO, 2020; Mehrotra & Panchamukhi, 2020)।

6. चुनौतियाँ (Major Challenges Highlighted in Literature)

ग्रामीण शिक्षा पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि वर्षों से कई योजनाओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में अनेक गंभीर बाधाएँ बनी हुई हैं। प्रमुख चुनौतियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

A. संसाधनों की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विद्यालयों में बुनियादी ढाँचा अत्यंत कमजोर है। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, बिजली और खेलकूद की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। शिक्षण-सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शिक्षक-छात्र अनुपात भी अक्सर असंतुलित होता है, जिससे व्यक्तिगत मार्गदर्शन असंभव हो जाता है।

B. तकनीकी अंतराल (Digital Divide): डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के बावजूद ग्रामीण शिक्षा टेक्नोलॉजी के साथ बराबरी नहीं कर पाई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, स्मार्ट डिवाइसों का अभाव और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा तक समान पहुँच नहीं हो पाती। कोविड-19 महामारी के दौरान यह अंतराल विशेष रूप से उजागर हुआ।

C. उच्च ड्रॉपआउट दर

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर माध्यमिक स्तर के बाद विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं—

- आर्थिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ
- बाल मजदूरी
- शिक्षा की अप्रासंगिकता की धारणा
- परिवहन और दूरस्थ विद्यालय

- किशोरावस्था में विवाह की सामाजिक प्रथा
- ड्रॉपआउट दर लड़कियों के बीच और भी अधिक पाई जाती है।

D. प्रवासी एवं जनजातीय समुदायों की विशेष समस्याएँ: मौसमी प्रवास, भाषा की भिन्नता, रोजगार आधारित विस्थापन और सामाजिक अलगाव के कारण इन समुदायों के बच्चों की शिक्षा निरंतर नहीं रह पाती। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़ी शिक्षण सामग्री की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार पढ़ाई छोड़ने की मुख्य वजह यह होती है कि बच्चा नए स्थान या विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाता।

E. निगरानी एवं मूल्यांकन की कमी: शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और नियमित निगरानी का अभाव देखा गया है। विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (SMC), पंचायतें और शैक्षिक अधिकारी कई बार अपेक्षित स्तर पर सक्रिय नहीं होते। परिणामस्वरूप—

- योजनाएँ कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं,
- छात्र उपस्थिति और प्रदर्शन का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता,
- सुधारात्मक कदमों में देरी होती है।

7. अच्छी प्रथाएँ और मॉडल (Best Practices & Case Studies)

ग्रामीण शिक्षा में चुनौतियों के बावजूद कई राज्यों और जिलों ने स्थानीय संदर्भों और नवाचारों के माध्यम से सफल मॉडल विकसित किए हैं। ये सफलताएँ न केवल नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, बल्कि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूलन की संभावनाएँ भी प्रस्तुत करती हैं।

राज्य/जिला स्तर की सफल पहलें: कुछ राज्यों में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सफल कार्यक्रम लागू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु में पंचायत-आधारित शिक्षा प्रबंधन और स्कूल सुधार मॉनिटरिंग की पहल ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता और उपस्थिति को बढ़ाया है (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। इन पहलों में नियमित मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों के सीखने के परिणाम बेहतर हुए हैं।

सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल: ग्रामीण शिक्षा में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देने वाले मॉडल ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। स्कूल प्रबंधन समितियाँ (SMC) और माता-पिता शिक्षक संघ जैसे कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि अभिभावक बच्चों की उपस्थिति, पाठ्य-सामग्री और अवसंरचना की निगरानी कर सकें (Govinda & Bandyopadhyay, 2011)। कुछ जिलों में स्थानीय स्वयंसेवी समूहों ने बच्चों के लिए ट्यूटरिंग, छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे न केवल सीखने की निरंतरता बनी बल्कि स्कूल में रुचि भी बढ़ी।

वैकल्पिक एवं नवाचारपूर्ण शिक्षण प्रणालियाँ: कुछ NGO और शैक्षिक संस्थान नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, गतिविधि-आधारित अधिगम और बहुभाषी शिक्षण मॉड्यूल ग्रामीण बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने में प्रभावी साबित हुए हैं (Pratham, 2020)। ऐसे मॉडल बच्चों को रटने की बजाय समझने और अनुभव के माध्यम से सीखने पर प्रेरित करते हैं, जिससे सीखने के परिणाम बेहतर और टिकाऊ होते हैं।

डिजिटल और मोबाइल आधारित समाधान: डिजिटल और मोबाइल तकनीक का प्रयोग ग्रामीण शिक्षा में तेजी से बढ़ा है। स्मार्ट क्लासेस, मोबाइल-आधारित लर्निंग एप्स और वीडियो लेसन जैसी पहलों ने कठिन भौगोलिक और संसाधन-संबंधी बाधाओं को आंशिक रूप से कम किया है (UNICEF, 2021; Mustafa, 2024)। इन समाधानों के माध्यम से बच्चों को दूरदराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों की प्रगति पर नजर रखने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

समग्र रूप से, इन सफल मॉडल और नवाचार ग्रामीण शिक्षा के लिए प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनका अनुकूलन, विस्तार और सतत मूल्यांकन न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकता है, बल्कि नीति-निर्माण और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देश भी प्रदान कर सकता है (Mehrotra & Panchamukhi, 2020; UNICEF, 2021)।

8. शोध अंतर (Research Gaps)

ग्रामीण शिक्षा पर उपलब्ध साहित्य और नीतिगत रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध का अभाव है, जिससे नीति और अभ्यास दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

अपर्याप्त डेटा या क्षेत्रीय अध्ययन: ग्रामीण शिक्षा के कई पहलुओं पर पर्याप्त डेटा नहीं है, विशेषकर दूरदराज और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में। अधिकांश शोध बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षणों या सीमित राज्य स्तर के आंकड़ों पर आधारित हैं, जिससे स्थानीय संदर्भ और विविधता का समुचित चित्र नहीं मिलता (Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। ऐसे क्षेत्रीय अध्ययन नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव और उनकी उपयुक्तता का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायक हो सकते हैं।

शिक्षण परिणामों पर कम फोकस: हालांकि नामांकन और अवसंरचना पर कई अध्ययन उपलब्ध हैं, पर सीखने के परिणामों (learning outcomes) पर गहन और तुलनात्मक शोध सीमित है। बच्चों की समझ, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और रचनात्मक सोच जैसी क्षमताओं का निरंतर मूल्यांकन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है (ASER Centre, 2024)। इस कमी के कारण नीति-निर्माण और स्कूल सुधार कार्यक्रम अक्सर केवल नामांकन या अवसंरचना तक सीमित रह जाते हैं।

तकनीकी पहुँच और प्रभाव पर सीमित साहित्य: डिजिटल शिक्षा और ICT आधारित हस्तक्षेप ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक प्रभाव, पहुँच और प्रभावशीलता पर साहित्य सीमित है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपकरण की उपलब्धता और शिक्षकों तथा बच्चों की डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में ठोस शोध अभी भी अपर्याप्त है (Mustafa, 2024; UNICEF, 2021)।

मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा और बालिका शिक्षा पर अंतराल: ग्रामीण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा (inclusive education) और बालिका शिक्षा के विशेष मुद्दों पर भी पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। बालिका शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कारकों का गहरा प्रभाव होता है, पर उनका व्यवस्थित आकलन अभी भी कम हुआ है (UNICEF, 2021; Govinda & Bandyopadhyay, 2011)। इसी प्रकार, विशेष शिक्षा की जरूरत वाले बच्चों के लिए रणनीति और संसाधनों का प्रभाव भी व्यापक रूप से मूल्यांकित नहीं किया गया है।

समग्र रूप से देखा जाए तो ये शोध अंतर नीति-निर्माण, योजना क्रियान्वयन और नवाचारपूर्ण हस्तक्षेपों के लिए चुनौती पेश करते हैं। इन्हें भरने के लिए क्षेत्रीय, तुलनात्मक और विषय-विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है, जो ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को प्रभावी रूप से बढ़ा सके (Mehrotra & Panchamukhi, 2020; ASER Centre, 2024)।

9. सुझाव और भविष्य की दिशा (Recommendations & Future Directions)

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बेहतर बनाने के लिए बहुस्तरीय और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। विभिन्न शोधों और सफल मॉडलों के आधार पर कुछ प्रमुख सुझाव निम्नानुसार दिए जा सकते हैं।

अवसंरचना सुधार: ग्रामीण विद्यालयों में भौतिक और शैक्षिक अवसंरचना को सुधारना अनिवार्य है। पर्याप्त कक्षाएँ, बिजली, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ बच्चों के सीखने के अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं (UDISE+, 2023; Mehrotra & Panchamukhi, 2020)। इन संसाधनों की उपलब्धता न केवल छात्र उपस्थिति बढ़ाती है, बल्कि शिक्षकों की कार्यक्षमता और सीखने की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है।

प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति: शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों की नियमित नियुक्ति आवश्यक है। सतत व्यावसायिक विकास, स्थानीय संदर्भ की समझ और बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों पर प्रशिक्षण ग्रामीण शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं (UNESCO, 2020)। इसके अलावा, शिक्षक अनुपस्थिति और कार्यभार संतुलन पर ध्यान देने से शिक्षा का निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है।

डिजिटल सशक्तिकरण: डिजिटल शिक्षा और ICT आधारित संसाधनों का समावेश ग्रामीण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट उपकरण और शिक्षक-छात्रों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण से ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा की पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ सकती है (Mustafa, 2024; UNICEF, 2021)। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल शिक्षा के स्तर को सुधार सकता है, बल्कि छात्रों की तकनीकी साक्षरता और 21वीं सदी के कौशलों के विकास में भी सहायक है।

सामुदायिक एवं अभिभावक सहभागिता: स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावक संघ और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना आवश्यक है। इससे बच्चों की नियमित उपस्थिति, पाठ्य-सामग्री की गुणवत्ता और स्कूल के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है (Govinda & Bandyopadhyay, 2011)। सामुदायिक निगरानी और अभिभावक सहभागिता से बच्चों के सीखने के परिणाम और स्कूल सुधार की संभावना बढ़ती है।

नीति कार्यान्वयन की मजबूती: नीति और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट लक्ष्यों, समयबद्ध योजनाओं और प्रशासनिक समर्थन की आवश्यकता है। सरकारी और निजी हस्तक्षेपों में समन्वय, संसाधनों का उचित वितरण और स्थानीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलन से नीति की प्रभावशीलता बढ़ सकती है (UNESCO, 2020; Mehrotra & Panchamukhi, 2020)।

Monitoring & Evaluation Models: सतत मूल्यांकन और निगरानी (monitoring & evaluation) मॉडल ग्रामीण शिक्षा सुधार की कुंजी हैं। नियमित डेटा संग्रह, स्कूल स्तर पर निरीक्षण, लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र सुधारात्मक उपायों को समय पर लागू करने में मदद करता है (ASER Centre, 2024)। इसके माध्यम से योजनाओं का प्रभाव मापा जा सकता है और सुधारात्मक हस्तक्षेप शीघ्र लागू किए जा सकते हैं।

समग्र रूप से, इन सुझावों का पालन ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देने और नवाचारपूर्ण उपाय अपनाने से ग्रामीण शिक्षा की स्थिति में दीर्घकालिक सुधार संभव है।

10. निष्कर्ष (Conclusion)

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी अनेक संरचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्तता, पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल अंतराल और सामाजिक बाधाएँ ग्रामीण बच्चों के सीखने के अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। साथ ही, नीति-हस्तक्षेपों और योजनाओं के प्रभाव का समुचित मूल्यांकन और स्थानीय संदर्भों में अनुकूलन भी अब तक सीमित रहा है (Mehrotra & Panchamukhi, 2020; ASER Centre, 2024)।

हालांकि, सफल मॉडल और नवाचारपूर्ण पहलें यह दर्शाती हैं कि सामुदायिक सहभागिता, डिजिटल समाधान, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और सतत मूल्यांकन के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा में वास्तविक सुधार संभव है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें नीति, संसाधन, शिक्षक क्षमता, तकनीकी पहुँच और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का समेकित प्रबंधन शामिल हो।

भविष्य में शोध और नीतिगत हस्तक्षेपों को इन पहलुओं पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि ग्रामीण शिक्षा केवल नामांकन तक सीमित न रहे, बल्कि सीखने के वास्तविक परिणामों और बच्चों के समग्र विकास को भी सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार, ग्रामीण शिक्षा में सुधार केवल बच्चों की शैक्षिक क्षमता बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है (UNESCO, 2020; UNICEF, 2021)।

सन्दर्भ सूची

ASER Centre. (2024). *Annual Status of Education Report (Rural) 2023*. New Delhi: Pratham.

Census of India. (2011). *Provisional population totals: India*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

Drèze, J., & Goyal, A. (2003). *Future of mid-day meals*. Economic and Political Weekly, 38(44), 4673–4683.

FICCI. (2019). *Corporate social responsibility initiatives in education: A report*. New Delhi: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

Govinda, R., & Bandyopadhyay, M. (2011). *Education and social inclusion in India: Policies and practices in rural and tribal areas*. International Journal of Educational Development, 31(6), 564–571. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.03.006

Govt. of India. (2014). *Sarva Shiksha Abhiyan Framework 2014*. Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Kremer, M., Brannen, C., & Glennerster, R. (2005). Teacher absence in India: A snapshot. *Journal of the European Economic Association, 3*(2-3), 658–667. https://doi.org/10.1162/1542476053270157

Mehrotra, S., & Panchamukhi, P. (2020). *Education in rural India: Challenges and policy interventions*. New Delhi: Routledge India.

Ministry of Education, Govt. of India. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan: Guidelines for implementation*. New Delhi: Department of School Education and Literacy.

Mohanty, A., & Panda, M. (2015). Multilingual education in India: Issues and challenges. *Language in India, 15*(7), 1–14.

Mustafa, N. (2024). Digital learning in rural India: Opportunities and barriers post-COVID-19. *International Journal of Educational Technology, 11*(2), 45–61.

Pratham. (2020). *Annual report on innovations in rural education*. New Delhi: Pratham Education Foundation.

Stelmach, B. (2011). Rural education development: Conceptual foundations and policy perspectives. *International Review of Education, 57*(4), 451–470. https://doi.org/10.1007/s11159-011-9245-2

UNESCO. (2004). *Education for all global monitoring report: The quality imperative*. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education*. Paris: UNESCO Publishing.

UNICEF. (2021). *Digital learning and equity in rural education: India country report*. New Delhi: UNICEF India.

UDISE+. (2023). *Unified District Information System for Education (UDISE+) 2022–23*. Ministry of Education, Government of India.